राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 1670/2017

विनोद कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी वार्ड नंबर 5, खानुवाली, थाना- रावला, जिला श्रीगंगानगर, वर्तमान में उप जेल अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर में कैद।

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री जगमाल सिंह चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी की सहायता से
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री बी.आर. बिश्नोई, पी.पी.

माननीय श्री न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

सी ए वी निर्णय

सुरक्षित रखा : 06/03/2024

फैसला सुनाया गया : 05/04/2024

रिपोर्ट करने योग्य

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या	पैरा संख्या
1	प्रस्तावना	2 से 4	1 से 9
2	अभियुक्त-अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ	4 से 16	10 से 43
3	राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ	16 से 19	44 से 55
4	विश्लेषण	19 से 42	56 से 116
5	निष्कर्ष	42 से 44	117 से 123

1. धारा 374 के तहत यह अपील विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपगढ़ कैंप घड़साना, जिला श्रीगंगानगर (जिसे आगे “ट्रायल कोर्ट” कहा जाएगा) द्वारा सत्र मामला संख्या 13/2014 में दिनांक 22.09.2017 को पारित निर्णय और सजा के

खिलाफ है, जिसके तहत आरोपी-अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 449 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता, जिसे अंततः इस मामले में आरोपी पाया गया, ने पुलिस स्टेशन रावला में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें कहा गया कि जब वह 30.05.2014 की सुबह लगभग 7-8 बजे अपने भाई राजेश के घर अपने बर्तन वापस लेने गया, तो उसने गेट बंद पाया और गेट से झांकने पर उसने देखा कि उसका भाई बिस्तर पर पड़ा था और उसके सिर पर कुछ चोटें थीं। इसमें यह भी कहा गया था कि उसने फिर पड़ोसियों को बुलाया और पाया कि उसके भाई के सिर पर किसी तेज धार वाले हथियार से हमला किया गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी।

3. लिखित सूचना के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 449 और 302 के तहत एफआईआर संख्या 112/2014 दर्ज की गई।

4. जांच के दौरान जांच अधिकारी ने विभिन्न गवाहों के बयान दर्ज किए और कुछ साक्ष्य एकत्र किए, जिसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मृतक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं सूचनाकर्ता - वर्तमान अपीलकर्ता ने की है।

5. सामान्य जांच के बाद पुलिस ने आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घड़साना की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद मामला ट्रायल कोर्ट को सौंप दिया गया।

6. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 449 के तहत अपराध के लिए 05.01.2015 को आरोप तय किए। आरोपी ने आरोपों से इनकार किया और ट्रायल की मांग की।

7. ट्रायल के दौरान, 22 गवाह गवाह बॉक्स में पेश हुए और अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए 54 दस्तावेज पेश किए गए और प्रदर्शित किए गए। अपीलकर्ता का बयान धारा 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया, जिसने उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया और निर्दोष होने का दावा किया और तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है।

8. पक्षों की सुनवाई के पश्चात विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त-अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाया तथा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 449 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया तथा धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा तथा

1000/- रूपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई। धारा 449 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध करने के लिए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 1000/- रूपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा अलग से सुनाई गई, तथापि यह शर्त रखी गई कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जगमाल सिंह चौधरी ने अपने तर्कों से न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलकर्ता को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराया गया है, क्योंकि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। उन्होंने कहा कि हथियार की बरामदगी, कपड़ों की बरामदगी, अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य और न्यायेतर स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त-अपीलकर्ता के खिलाफ मामला सिद्ध पाया गया है, जबकि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका कि अपीलकर्ता ने मृतक की हत्या की है। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने हत्या के पीछे जो मकसद पाया है, वह भी काल्पनिक है और इसलिए अभियुक्त-अपीलकर्ता को दी गई सजा और दोषसिद्धि रद्द की जानी चाहिए और उसे अपास्त किया जाना चाहिए।

<u>अभियुक्त-अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष के मामले को प्रत्येक आधार पर ध्वस्त करने के लिए व्यापक तर्क प्रस्तुत किए, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

<u>(a) हथियार की बरामदगी:</u>

11. सर्वप्रथम न्यायालय को कुल्हाड़ी की बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श पी/5) के माध्यम से यह बताते हुए कि कुल्हाड़ी की बरामदगी पुलिस अभिरक्षा में अपीलकर्ता के घर से की गई है, संभवतः सुभाष (पी.डब्लू.2) और ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9) की उपस्थिति में। तत्पश्चात, उन्होंने न्यायालय को उपरोक्त व्यक्तियों सुभाष (पी.डब्लू.2) और ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9) के बयानों के माध्यम से अवगत कराया और इस बात पर जोर दिया कि सुभाष (पी.डब्लू.2) ने केवल यह कहा था कि पुलिस ने आरोपी के घर के आंगन से कुल्हाड़ी बरामद की थी और बरामदगी ज्ञापन (फर्द-प्रत्यक्ष 5) तैयार किया था, बिना यह बताए कि क्या अपीलकर्ता ने ही उस स्थान का खुलासा किया था जहां कुल्हाड़ी छिपाई गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि उक्त गवाह ने यह भी नहीं बताया कि बरामद होने के बाद कुल्हाड़ी को पैक करके सील कर दिया गया था। इसके बाद विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ओम प्रकाश

(पी.डब्लू. 9) के बयान के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराया और प्रस्तुत किया कि इस गवाह के अनुसार अपीलकर्ता ने घर के उस हिस्से से कुल्हाड़ी निकाली और उसे सौंप दिया, जहां कई कृषि उपकरण पड़े थे।

12. उन्होंने दलील दी कि इन अधूरे बयानों के साथ कुल्हाड़ी की बरामदगी को कानूनी तौर पर साबित नहीं कहा जा सकता। और चूंकि खून से सनी कुल्हाड़ी - जिसे अपराध का हथियार बताया जा रहा है - की बरामदगी ठीक से साबित नहीं हुई है, इसलिए ऐसी बरामदगी के आधार पर अपीलकर्ता की दोषसिद्धि न्यायिक जांच में टिक नहीं सकती।

(b) कपड़ों की बरामदगी:

13. कपड़ों की बरामदगी के मामले में प्रदर्श पी/6 के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त बरामदगी भी प्लांटेड थी, क्योंकि दिनांक 05.06.2014 के बरामदगी ज्ञापन से पता चलता है कि अपीलकर्ता ने एक काले रंग की पूरी आस्तीन की शर्ट सौंपी थी, जिसके सामने की तरफ खून के निशान थे और एक सफेद रंग की खून से सनी पैंट थी। उन्होंने दर्शाया कि सुभाष (पी.डब्लू.2) ने यह नहीं बताया है कि दिनांक 05.06.2014 के बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श पी/6) के माध्यम से बरामद किए गए कपड़े पैक और सील किए गए थे और तर्क दिया कि ऐसी कमजोरी के कारण कपड़ों की बरामदगी को त्याग दिया जाना चाहिए।

(c) बरामदगी में देरी:

14. जांच अधिकारी प्रहलाद राम (पी.डब्लू. 21) के बयान के संबंध में, जहां तक कुल्हाड़ी, कथित अपराध का हथियार और कपड़ों की बरामदगी का सवाल है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ये बरामदगी घटना के पांच दिन बाद की गई है और वह भी आरोपी-अपीलकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, जब वह पुलिस हिरासत में था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हथियार और कपड़े भी साजिश के तहत रखे गए थे और इकबालिया बयान बलप्रयोग और दबाव से प्राप्त किया गया है।

(d) अपराध के कपड़े और हथियार पर खून के धब्बे:

15. श्री चौधरी ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि जांच अधिकारी ने आरोपी-अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया था और झूठी बरामदगी की योजना बनाई थी। उन्होंने अदालत का ध्यान रिकवरी मेमो के उस हिस्से की ओर आकर्षित किया जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि दोनों कपड़े पहले से ही धुले हुए

थे और तर्क दिया कि जब बरामद कपड़े धुले हुए पाए गए, तो यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि खून के धब्बे देखे जा सकते हैं या नोट किए जा सकते हैं, वह भी एक शर्ट पर, जो काले रंग की थी। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि यदि आरोपी-अपीलकर्ता ने अपराध करने के समय पहने हुए कपड़े धोए थे, तो, वह अपराध के हथियार होने के नाते कुल्हाड़ी को क्यों नहीं धोएगा? यह किसी की समझ से परे है।

16. विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर भी जोर दिया कि अपीलकर्ता को दिनांक 03.06.2014 को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद हथियार/बरामदगी की जानकारी दिनांक 04.06.2014 को प्रातः 08.15 बजे दी गई तथा कपड़ों के बारे में खुलासा कथन दिनांक 05.06.2014 को प्रातः 09.10 बजे दिया जाना दर्शाया गया है, जबकि दोनों वस्तुओं की बरामदगी दिनांक 05.06.2014 को हुई। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपराध के हथियार की बरामदगी में 24 घंटे की देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

(e) रक्त समूह के संकेत का अभाव:

17. तत्पश्चात, विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को प्रदर्श पी/47-एफ.एस.एल. रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया तथा कहा कि अभियुक्त द्वारा पहने गए पैंट की एफ.एस.एल. रिपोर्ट, जहां तक रक्त का पता लगाने का संबंध है, सकारात्मक रिपोर्ट देती है तथा 'ए.बी.' समूह के मानव रक्त की उपस्थिति का संकेत देती है, जबकि शर्ट और कुल्हाड़ी की एफ.एस.एल. रिपोर्ट में रक्त की मौजूदगी दिखाई गई है, लेकिन रक्त समूह के संबंध में अनिर्णायक है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हो सकता है, मृतक का रक्त समूह 'ए.बी.' था तथा अपीलकर्ता की पैंट से मिले रक्त के निशान भी मृतक के रक्त समूह के समान रक्त को दर्शाते हैं, लेकिन यह अपीलकर्ता को अपराध का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकता।

(f) अभियुक्त के रक्त समूह की जांच न करवाना:

18. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता के रक्त समूह की जांच नहीं करवाई और इसलिए एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी/47 के आधार पर उसे दोषी ठहराना कानून की स्थिति के विपरीत है, जैसा कि निम्नलिखित निर्णयों में तय किया गया है:

(i) 1996 आरसीसी पी. 12 (अब्दुल हामिद एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य) पैरा-16

(ii) (2008) 4 आरएलडब्लू 3490; 2008 2 क्रि.एल.आर. (राज.) 1701 (भंवर लाल @ भंवरा बनाम राजस्थान राज्य) पैरा-5, 6, 12, 13 और 15

(iii) (2011) 12 एससीसी 258 (सुनील राय बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़) पैरा-10, 29 और 30)

(g) अंतिम बार देखा गया:

19. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है, क्योंकि उसे 29 मई, 2014 की रात में मृतक के घर के आसपास देखा गया था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ओम प्रकाश (पी.डब्लू. 9) एकमात्र गवाह है, जिसने दावा किया है कि उसने आरोपी - अपीलकर्ता को घटना से पहले रात यानी 29.05.2014 को लगभग 11.30 - 11.45 बजे देखा था। मुख्य परीक्षा के प्रासंगिक भाग और ओम प्रकाश (पी.डब्लू. 9) की जिरह को पढ़ते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस गवाह की गवाही को खारिज किया जा सकता है क्योंकि अपीलकर्ता और उसके बीच पहले से दुश्मनी थी। विद्वान वकील ने दलील दी कि यह गवाह बहुत ही चतुर गवाह है, जिसने अपने बयान में सुधार किया है और धारा 164 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में जो कुछ उसने नहीं कहा था, उसे अदालत में साक्ष्य देते समय जोड़ दिया गया है, जाहिर है, उसके बयान में कमी को छिपाने के लिए। उन्होंने दलील दी कि यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि 52 साल का व्यक्ति रात में किसी दूसरे व्यक्ति को पहचान सकता है, वह भी बिना रोशनी वाली सड़क पर।

20. इस बात पर जोर देते हुए कि इस गवाह की गवाही खारिज किए जाने योग्य है, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि भले ही यह सही माना जाए कि अपीलकर्ता मृतक के घर के सामने घूम रहा था, लेकिन उसे मृतक के साथ आखिरी बार देखे जाने के कारण अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

21. विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने "अंतिम बार देखे जाने" के सिद्धांतों को समझने में गंभीर गलती की है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ओम प्रकाश (पी.डब्लू. 9) की गवाही के अनुसार, अपीलकर्ता मृतक के घर के आसपास घूमता हुआ पाया गया था, लेकिन मृतक के साथ नहीं (जिसकी उस रात उसके घर के अंदर हत्या कर दी गई थी)। विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि साइट मैप के अनुसार, अपीलकर्ता और मृतक के घर एक दूसरे के सामने हैं और तर्क दिया कि मृतक के घर के बाहर अपीलकर्ता की उपस्थिति उसके अपने घर से काफी बाहर थी और इसलिए, उसका चलना अप्राकृतिक या संदिग्ध नहीं माना जा सकता।

22. विद्वान वकील ने ओम प्रकाश (पी.डब्लू. 9) के बयान को पूरा पढ़ा और विभिन्न विसंगतियों की ओर इशारा किया जैसे कि उसके हाथ में टॉर्च होना और कुत्तों की उपस्थिति, जो धारा 161 सीआरपीसी के तहत उसके बयान में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थी और तर्क दिया कि उसकी गवाही विश्वास पैदा नहीं करती है।

23. अंतिम बार देखे गए साक्ष्य के संबंध में अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया:-

(i) (2011) 12 एससीसी 258,

सुनील राय उर्फ पौना एवं अन्य बनाम यूटी चंडीगढ़, हेड नोट ए।

(ii) (2015) 12 एससीसी 644,

विजय शंकर बनाम हरियाणा राज्य, पैरा 13

(iii) (2002) 8 एससीसी 45,

बोध राज उर्फ बोधा एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य।

(iv) डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 135/1995 दिनांक 13.10.2023 को निर्णीत श्रीमती लीला बनाम राजस्थान राज्य, पैरा संख्या 24 एवं 25।

(h) न्यायेतर स्वीकारोक्ति:

24. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायेतर स्वीकारोक्ति के बारे में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष की भी बहुत आलोचना की, क्योंकि उनके अनुसार विद्वान ट्रायल कोर्ट ने न्यायेतर स्वीकारोक्ति की अवधारणा और सिद्धांतों को पूरी तरह से गलत समझा था। उन्होंने तर्क दिया कि ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9) और निहाल चंद (पी.डब्लू.11) की गवाही में जो स्वीकारोक्ति आई है, उसे कानून की नजर में स्वीकारोक्ति नहीं कहा जा सकता। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोनों गवाहों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 05.06.2014 को जब अपीलकर्ता पुलिस के साथ आया था, तो उससे पूछा गया था कि उसने क्या किया है? और तभी आरोपी-अपीलकर्ता ने अपने भाई की हत्या करने का अपराध स्वीकार किया था।

25. निहाल चंद (पी.डब्लू.11) के बयान के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस गवाह के अनुसार भी, अपीलकर्ता ने 5 और 6 जून, 2014 को पुलिस के साथ आने पर सभी के सामने अपनी गलती स्वीकार की थी।

26. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सबसे पहले तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9) और निहाल चंद (पी.डब्लू.11) के समक्ष अपना अपराध स्वीकार

करने का कोई अवसर या कारण नहीं था, विशेषकर तब जब ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9) और अपीलकर्ता के बीच संबंध तनावपूर्ण थे - उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शत्रुतापूर्ण संबंध वाले व्यक्ति के समक्ष अपराध स्वीकार करना प्रश्न से बाहर है।

27. इस स्वीकारोक्ति पर विवाद करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि ऐसा स्वीकारोक्ति किया भी गया था, तो वह तब किया गया था जब अपीलकर्ता पुलिस हिरासत में था और इसलिए, यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के प्रावधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से आता है और अपीलकर्ता की कथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धि को खारिज किया जाना चाहिए।

28. न्यायेतर स्वीकारोक्ति के संबंध में अपने उपरोक्त तर्कों के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया:-

(i) (2011) 12 एससीसी 258,

सुनील राय उर्फ पौना एवं अन्य बनाम यू.टी. चंडीगढ़, हेड नोट बी

(ii) (1974) 4 एससीसी 747

जगता बनाम हरियाणा राज्य।

(iii) (2015) 12 एससीसी 644

विजय शंकर बनाम हरियाणा राज्य, हेड नोट सी

(iv) (2019) 2 आरएलडब्लू 1676

श्रवण राम नायक बनाम राजस्थान राज्य।

(v) 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी1400; 2022 एआईआर (एससी) पृष्ठ 5110

सुब्रमण्य बनाम कर्नाटक राज्य।

(vi) आपराधिक अपील संख्या 437/2016, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 20.07.2023 को निर्णीत

शत्रुघ्न बनाम छत्तीसगढ़ राज्य।

(vii) 2023 क्रि. एल. जे. पृष्ठ 1726

मुन्ना लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।

(i) मकसद:

29. श्री चौधरी ने प्रस्तुत किया कि मकसद निकालने के लिए, ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच एक भूमि विवाद था, जो

निष्कर्ष मुख्य रूप से ओम प्रकाश (पी.डब्लू. 9) की गवाही पर आधारित है। विद्वान वकील ने रेखांकित किया कि जांच अधिकारी (पी.डब्लू. 21) ने अपनी जिरह के दौरान स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मृतक और अपीलकर्ता के बीच कोई आपराधिक या सिविल मामला या शिकायत लंबित नहीं थी और यह भी कि वह किसी भी विवाद/मामले या यहां तक कि पंचायत को दर्शाने वाले किसी भी रिकॉर्ड का पता नहीं लगाया जा सका।

30. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे बताया कि जांच के दौरान जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता की बहन पुष्पा (पी.डब्लू.14) का बयान दर्ज किया और निष्कर्ष निकाला कि जमीन से संबंधित विवाद था, लेकिन जब उक्त गवाह गवाह के कठघरे में आया तो उसने अभियोजन पक्ष की कहानी को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने दलील दी कि हालांकि उक्त गवाह पी.डब्लू.-14 (अपीलकर्ता की बहन) को अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन न करने के लिए पक्षद्रोही घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी, इस तथ्य पर ध्यान देने की जरूरत है कि उसने किसी भी विवाद के तथ्य से स्पष्ट रूप से इनकार किया है।

31. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अन्य स्वतंत्र गवाहों, देवी लाल (पी.डब्लू.7), मंगतू राम (पी.डब्लू.6) और मनी राम (पी.डब्लू.10) आदि ने भी दुश्मनी के तथ्य से इनकार किया है और केवल इसलिए कि उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच कोई विवाद था और इस विवाद के लिए ही अपीलकर्ता ने मृतक की हत्या की थी।

32. मकसद के संबंध में अपने उपरोक्त तर्कों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया:-

(I) (2015) 12 एससीसी 644

विजय शंकर बनाम हरियाणा राज्य, हेड नोट बी

(ii) (2016) 16 एससीसी 192

पंकज बनाम राजस्थान राज्य

(iii) 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1454

नंदू सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य।

(j) बयान दर्ज करने में देरी:

33. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यद्यपि एफआईआर 30.05.2014 को दर्ज की गई थी, लेकिन उसी गांव के गवाहों के बयान बहुत देर

से दर्ज किए गए थे, उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9) का बयान धारा 161 सीआरपीसी (प्रदर्श डी/1) के तहत 30.06.2014 को दर्ज किया गया था, जबकि महावीर (पी.डब्लू.15) और राम चंद्र (पी.डब्लू.16) (अपीलकर्ता के पड़ोसी) का बयान 06.07.2014 को (प्रदर्श डी/4 और प्रदर्श डी/5) दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा अन्य गवाहों के बयान भी तुरंत दर्ज नहीं किए गए थे।

34. बयान दर्ज करने में देरी को उजागर करते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि एक गवाह ने जांच अधिकारी को सूचित किया था कि उसने अपीलकर्ता को मृतक के घर के सामने देखा था और उनमें से कुछ ने पिछली दुश्मनी के बारे में बताया था, लेकिन इस तरह के साक्ष्य भी जांच अधिकारी के ध्यान में आए, जब उपरोक्त संदर्भित व्यक्तियों, ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9), महावीर (पी.डब्लू.15) और राम चंद्र (पी.डब्लू.16) के बयान दर्ज किए गए।

35. यह याद दिलाते हुए कि अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दी गई जानकारी के आधार पर अपराध का हथियार और कपड़े 05.06.2014 को बरामद किए गए थे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इन गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी से जांच की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है, और यह इस बात का संकेत है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता को फंसाने के लिए झूठे गवाहों को खड़ा किया गया है।

36. अपने इस तर्क के समर्थन में कि गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने (2004) 10 एससीसी 583 में रिपोर्ट किए गए विजयभाई भानाभाई पटेल बनाम नवनीतभाई नाथूभाई पटेल के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

(k) डॉग स्क्वायड की रिपोर्ट को दबाना:

37. यह भी तर्क दिया गया कि यद्यपि डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया गया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं की गई। न्यायालय को यह संतुष्ट करने के लिए कि डॉग स्क्वायड को बुलाया गया था, श्री चौधरी ने न्यायालय को गवाहों अर्थात् सुनील कुमार (पी.डब्लू.18) और किस्तुरा राम (पी.डब्लू.20) के बयान के प्रासंगिक भाग के माध्यम से और फिर, जांच अधिकारी - प्रहलाद राम (पी.डब्लू.21) के बयान की ओर ले गए और बताया कि जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि डॉग स्क्वायड की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

38. विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि यदि अपीलकर्ता अपराधी होता, तो प्रशिक्षित कुत्ते निश्चित रूप से उसकी पहचान कर लेते, क्योंकि वह निश्चित रूप से डॉग स्क्वायड के आने पर मौजूद था। उन्होंने तर्क दिया कि यह तथ्य कि कुत्ते अपीलकर्ता की गंध को पहचानने में विफल रहे, जिससे पता चलता कि वह अपराध में शामिल था, अपीलकर्ता की बेगुनाही साबित करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच अधिकारी ने जानबूझकर डॉग स्क्वायड की रिपोर्ट को चार्जशीट के हिस्से के रूप में पेश नहीं किया क्योंकि यह 'नकारात्मक' थी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट न देना, बल्कि उसे रोके रखना यह दर्शाता है कि जांच अधिकारी ने निष्पक्ष जांच नहीं की।

(l) चोटों का आकार:

39. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चौधरी ने शत्रुघ्न (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, विशेष रूप से पैरा-19 में अपने तर्क को आगे बढ़ाने के लिए कहा कि चोट का आकार एक प्रासंगिक कारक है जिस पर विचार किया जाना चाहिए और यदि अपराध के हथियार का आकार और चोट का आकार मेल नहीं खाता है, तो आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। डॉक्टर (पी.डब्लू.12) के बयान की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चोटों की लंबाई और आकार लगभग 1 इंच है, जबकि कुल्हाड़ी का तेज हिस्सा 11.5 सेमी था और तर्क दिया कि चोटों का आकार अपराध के हथियार के आकार से मेल नहीं खाता है और चोटें उस हथियार से नहीं हो सकती हैं जो कथित तौर पर अपीलकर्ता से बरामद किया गया है और मृतक के सिर पर चार चोटें पहुंचाने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया है।

(m) अन्य तर्क:

40. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सामान्य उत्साह के साथ कुछ सहायक तर्क भी प्रस्तुत किए गए, जिन्हें इस पैराग्राफ में संक्षेप में उल्लेखित किया जा रहा है:

(i) गिरफ्तारी अवैध थी: 03.06.2014 तक जांच अधिकारी के पास अपीलकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए कोई कारण या सामग्री नहीं थी और फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद साक्ष्य तैयार किए गए और झूठी बरामदगी की गई। इकबालिया बयान प्राप्त करने और अपीलकर्ता को अवैध हिरासत में रखने के अलावा, श्री चौधरी ने तर्क दिया कि गवाहों के बयानों के अनुसार, जो 03.06.2014 तक दर्ज किए गए थे, जांच अधिकारी के ध्यान में आया था कि अपीलकर्ता के व्यवहार या शारीरिक भाषा से पता चलता है कि उसे हत्यारे के बारे में जानकारी/ज्ञान था। 03.06.2014 तक दर्ज किए गए बयानों के आधार पर

न्यायालय को अवगत कराते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि तब तक जांच अधिकारी के संज्ञान में कोई तथ्य या सामग्री नहीं आई थी, जिससे यह विश्वास हो सके कि अपीलकर्ता ने ही अपने भाई की हत्या की है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि गिरफ्तारी ही अवैध थी, इसलिए गिरफ्तारी के बाद एकत्र किए गए सभी साक्ष्य अवैध थे और उनका उपयोग अभियुक्त-अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता।

(ii) एक से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति: साइट मैप, साइट निरीक्षण रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तस्वीरों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि निश्चित रूप से एक से अधिक व्यक्ति थे, जो शायद ताश खेल रहे थे और पूरी संभावना है कि अपीलकर्ता के अलावा किसी और ने मृतक की हत्या की हो।

(iii) चारदीवारी पर कोई खून के धब्बे नहीं मिले: विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार आरोपी-अपीलकर्ता की शर्ट और पैंट कुल्हाड़ी के वार के कारण खून से सने हुए थे और इसलिए, मृतक के घर की चारदीवारी, जो मिट्टी और रेत से लिपी हुई थी, साफ या बेदाग नहीं रह सकती थी, क्योंकि अपराधी चारदीवारी पर चढ़कर या चढ़ते हुए भाग गया था।

(iv) अभियुक्त स्वयं मुखबिर था: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि यह तथ्य कि अभियुक्त ने ही पुलिस को घटना की सूचना दी थी, स्पष्ट रूप से उसकी निर्दोषता का संकेत देता है।

41. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चौधरी ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि न तो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय है और न ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के मामले में अपेक्षित रूप से श्रृंखला का प्रत्येक भाग ठीक से जुड़ा हुआ है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि मृतक की हत्या केवल अपीलकर्ता ने ही की थी।

42. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता को जांच अधिकारी द्वारा झूठे साक्ष्य तैयार करके और फर्जी गवाहों को पेश करके फंसाया गया है, जो कानूनी जांच का सामना नहीं कर सके, फिर भी ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है और माना है कि अपीलकर्ता ने मृतक की हत्या की थी, बिना इस बात पर विचार किए कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य, जिसमें ओम प्रकाश (पी.डब्लू. 9) का साक्ष्य भी शामिल है, अविश्वसनीय और प्रेरित था।

43. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि चेन में प्रत्येक छल्ला ठीक से जुड़ा हुआ है, जबकि इस मामले में न केवल कनेक्शन, बल्कि छल्लों का भी अभाव है।

राज्य की ओर से दलीलें

44. विद्वान लोक अभियोजक ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि अपीलकर्ता को अपने भाई की हत्या करने के लिए सही ढंग से दोषी ठहराया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य अचूक हैं। उन्होंने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला साबित कर दिया है और चेन का प्रत्येक छल्ला ठीक से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे दलील दी कि आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए गए हैं।

45. अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए तर्कों का जवाब देते हुए विद्वान लोक अभियोजक ने बताया कि कई गवाहों, अर्थात् सुभाष (पी.डब्लू.2), श्याम लाल (पी.डब्लू.4), मंगतू राम (पी.डब्लू.6), देवी लाल (पी.डब्लू.7), ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9), निहाल चंद (पी.डब्लू.11), पुष्पा (पी.डब्लू.14), महावीर (पी.डब्लू.15) और राम चंद्र (पी.डब्लू.16) जिनके घर या जमीन मृतक के घर/जमीन के नजदीक हैं, ने गवाही दी है कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच कृषि भूमि को लेकर विवाद था।

46. उपर्युक्त गवाहों के बयानों के प्रासंगिक भाग को पढ़ने के बाद, विद्वान लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच पहले से दुश्मनी थी, इतनी कि मृतक कभी भी अपीलकर्ता के घर नहीं आता था, जो उसका सगा भाई था और निहाल चंद (पी.डब्लू.11) ने यहां तक कहा है कि मृतक कभी भी अपीलकर्ता के घर नहीं जाता था क्योंकि उसे आशंका थी कि अपीलकर्ता उसे जहर दे देगा। विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के पास अपने भाई को मारने का मकसद था। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए विद्वान लोक अभियोजक ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद अनवर हुसैन बनाम असम राज्य (2023 क्रि.एल.जे. (एस.सी.) 609 तथा सिंगापगु अंजैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2010) 9 एस.सी.सी. 799) के मामले में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया।

47. न्यायेतर स्वीकारोक्ति के संबंध में विद्वान लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि ओम प्रकाश (पी.डब्लू. 9) तथा निहाल चंद (पी.डब्लू. 11) के साक्ष्य यह

स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलकर्ता ने मृतक राजेश की हत्या करने का अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। विद्वान लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि अपराध करने की ऐसी स्वीकारोक्ति पर विश्वास किया जाना चाहिए तथा उसका स्वाभाविक प्रभाव होना चाहिए।

48. बरामदगी में विसंगतियों के तर्क का जवाब देते हुए, विद्वान लोक अभियोजक ने कहा कि सुभाष (पी.डब्लू.2) और ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9), जो कुल्हाड़ी और कपड़ों की बरामदगी के गवाह हैं, ने बरामदगी को स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है। और केवल इसलिए कि सुभाष (पी.डब्लू.2) ने यह बताना छोड़ दिया है कि कुल्हाड़ी और कपड़ों को बैग में पैक किया गया था और फिर सील कर दिया गया था, बरामदगी को अवैध या संदिग्ध नहीं बनाया जा सकता है, खासकर जब ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9) और जांच अधिकारी - प्रहलाद राम (पी.डब्लू.21) ने भी स्पष्ट शब्दों में यह बयान दिया है कि अपीलकर्ता द्वारा सौंपे जाने के बाद कुल्हाड़ी और कपड़े पैक और सील कर दिए गए थे। विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि यदि बरामदगी के गवाह मुकर जाते हैं, तो भी जांच अधिकारी बरामदगी को साबित कर सकता है।

49. इस तर्क का समर्थन करने के लिए, विद्वान लोक अभियोजक ने निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया:

(i) (1999) 4 एससीसी 370

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम जीत सिंह।

(ii) (1978) 4 एससीसी 435

मोदन सिंह बनाम राजस्थान राज्य।

50. विद्वान लोक अभियोजक ने रेखांकित किया कि एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से मानव रक्त दिखाई देता है और तर्क दिया कि मानव रक्त की उपस्थिति आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है, (2001) 2 एससीसी 205 में रिपोर्ट किए गए गुरा सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में।

51. विद्वान लोक अभियोजक ने आगे कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अपीलकर्ता का आचरण एक सुसंगत कारक है और यदि देवी लाल (पी.डब्लू. 7) के बयान को ध्यान में रखा जाए, तो यह स्पष्ट है कि अपने भाई के लिए चिंतित होने के बजाय, जिसकी लाश पड़ी थी, अपीलकर्ता-अभियुक्त अपने बर्तनों के बारे में अधिक चिंतित था, जो मृतक के घर में पड़े थे।

52. विद्वान लोक अभियोजक ने जोर देकर कहा कि निहाल चंद (पी.डब्लू. 11) की गवाही के अनुसार, मृतक कभी भी विनोद के घर नहीं जाता था और न ही खाना खाता था क्योंकि उसे आशंका थी कि विनोद उसे जहर दे देगा और तर्क दिया कि पिछली दुश्मनी और मकसद अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त और उपयुक्त रूप से साबित किया गया है।

53. इस तर्क को पुष्ट करने के लिए विद्वान लोक अभियोजक ने कर्नाटक राज्य बनाम सुवर्णम्मा मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2015 (1) एससीसी 323 में दिए गए निर्णय का हवाला दिया।

54. विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि चूंकि अभियुक्त अपीलकर्ता ने न तो इस बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया है कि गवाहों ने उसके खिलाफ गवाही क्यों दी, न ही उसने अपने खिलाफ पेश किए गए आरोप या सबूतों से इनकार किया है, इसलिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी जानी चाहिए।

55. श्री चौधरी की इस दलील के जवाब में कि जहां तक रक्त समूह का सवाल है, एफएसएल रिपोर्ट अनिर्णायक है, विद्वान लोक अभियोजक ने कहा कि फोरेंसिक प्रयोगशाला खून की मौजूदगी का पता लगा सकती है, भले ही कपड़े धोए गए हों, हालांकि, खून से सने कपड़े धोने के बाद रक्त समूह का पता नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट, जो कुल्हाड़ी और कपड़ों पर मानव रक्त की उपस्थिति दिखाती है, निर्णायक सबूत है और दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है।

विश्लेषण

56. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी गई तथा अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

57. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (1984) 4 एससीसी 116 में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के संबंध में स्वर्णिम सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जिन्हें आमतौर पर पंचशील के रूप में जाना जाता है। ये पंचशील हाल ही में मौलिक नियम बन गए हैं और इनका तत्परता से पालन किया जाता है। उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का एक लाभदायक संदर्भ यहां दिया जा सकता है:

"153. इस निर्णय का गहन विश्लेषण यह दर्शाएगा कि अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूर्णतः स्थापित होने से पूर्व निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूर्णतः स्थापित किया जाना चाहिए।

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया है कि संबंधित परिस्थितियां "अवश्य या होनी चाहिए" न कि "स्थापित हो सकती हैं"। "साबित किया जा सकता है" और "साबित किया जाना चाहिए या अवश्य होना चाहिए" के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य: (1973) 2 एससीसी 793: 1973 एससीसी (क्रि.) 1033: 1973 क्रि. एलजे 1783] में माना था, जहां टिप्पणियां की गई थीं: [एससीसी पैरा 19, पृष्ठ 807: एससीसी (क्रि.) पृष्ठ 1047] निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषी होना चाहिए, न कि केवल दोषी हो सकता है, इससे पहले कि अदालत उसे दोषी ठहराए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच मानसिक दूरी बहुत लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्या योग्य नहीं होना चाहिए,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, सिवाय उस परिकल्पना के जिसे साबित किया जाना है, और

(5) साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

58. इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक और प्रत्यक्ष साक्ष्य पर विचार करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे।

59. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर एक के बाद एक विचार करना उचित होगा।

A. हथियार की बरामदगी:

60. कुल्हाड़ी की बरामदगी फर्द (प्रदर्श-पी/5) से पता चलता है कि यह अपीलकर्ता द्वारा दी गई भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 (प्रदर्श-पी/46) के तहत दी गई जानकारी के आधार पर बनाया गया है। जांच अधिकारी के अलावा, दो स्वतंत्र गवाह सुभाष (पी.डब्लू.2) और ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9) बरामदगी को साबित करने के लिए पेश हुए थे। यह सच है कि सुभाष (पी.डब्लू.2) ने गवाही दी कि संबंधित कुल्हाड़ी आरोपी-अपीलकर्ता के यार्ड से बरामद की गई थी और बरामदगी ज्ञापन तैयार किया गया था, लेकिन वह किसी तरह यह उल्लेख करना भूल गया कि बरामदगी के बाद कुल्हाड़ी को पैक करके सील कर दिया गया था। लेकिन फिर, इस संबंध में ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9) की गवाही पूरी है; उन्होंने न केवल अपीलकर्ता के कहने पर कुल्हाड़ी बरामद होने का तथ्य सुनाया, बल्कि यह भी कहा कि अपीलकर्ता द्वारा सौंपी गई कुल्हाड़ी को जांच अधिकारी ने उसके सामने विधिवत पैक करके सील कर दिया था।

61. इसके अलावा, जांच अधिकारी ने सभी कोणों से बरामदगी को सही ढंग से साबित किया है और इसलिए, केवल अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक सुभाष (पी.डब्लू. 2) की ओर से बयान की कमी या चूक के कारण (कि बरामद कुल्हाड़ी उसके सामने पैक और सील की गई थी), यह नहीं कहा जा सकता है कि बरामदगी दोषपूर्ण है या कुल्हाड़ी को सीलबंद अवस्था में फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था।

B. कपड़ों की बरामदगी:

62. कुल्हाड़ी की बरामदगी के बारे में जो तर्क दिया गया था, वह कपड़ों की बरामदगी पर सवाल उठाने के लिए व्यावहारिक रूप से दोहराया गया था। कुल्हाड़ी की बरामदगी के बारे में तर्कों को खारिज करने के लिए हमने जो कारण दिए हैं, वे कपड़ों की बरामदगी के संबंध में भी समान रूप से लागू होते हैं। यह देखते हुए कि कुल्हाड़ी और कपड़ों की बरामदगी के गवाह एक ही व्यक्ति हैं, हम ऊपर पैरा संख्या 60 में पहले से ही जो देखा है उसे दोहराना नहीं चाहते हैं।

C. बरामदगी में देरी:

63. हमारे अनुसार, अपीलकर्ता का तर्क कि छिपी हुई कुल्हाड़ी के संबंध में सूचना 04.06.2014 को प्रातः 08:15 बजे दी गई थी और कपड़ों के बारे में सूचना 05.06.2014 को प्रातः 9:10 बजे दी गई थी, जबकि ये वस्तुएं 05.06.2014 को शाम को बरामद की गई थीं और हथियार और कपड़ों की बरामदगी में इतनी देरी (क्रमशः 30 घंटे और 5 घंटे) अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है, यह तथ्य देखते हुए कि पुलिस स्टेशन घटनास्थल से लगभग 22 से 25 किलोमीटर दूर है, कोई प्रभाव नहीं डालता। बरामदगी और प्रकटीकरण कथन के बीच एक दिन का समय अंतराल ग्रामीण क्षेत्रों में अनुचित नहीं माना जा सकता, जहां पुलिस स्टेशन नजदीक नहीं है।

64. हमारे अनुसार, पूछताछ जारी रखना और हर प्रासंगिक जानकारी एकत्र होने तक एक दिन तक इंतजार करना जांच अधिकारी का स्वाभाविक आचरण था। इसके अलावा, भले ही यह मान लिया जाए कि जांच अधिकारी की ओर से कोई चूक हुई है, लेकिन केवल यही बात वसूली को अवैध नहीं बनाती और अपीलकर्ता की सजा पर इसका असर नहीं डालती।

D. कपड़ों पर खून की मौजूदगी:

65. रिकवरी मेमो (प्रदर्श-पी/6) के अवलोकन से पता चलता है कि जब कपड़े बरामद किए गए थे, तब उन्हें धोया जा चुका था। रिकवरी मेमो और साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलकर्ता की शर्ट, जिसे उसने कथित तौर पर अपराध के समय पहना था, काले रंग की थी और पैंट सफेद रंग की थी। हमारे पास हैरान होने का हर कारण है कि एक आम आदमी सरसरी निगाह से कैसे दावा कर सकता है कि शर्ट, जो काले रंग की थी और पहले से ही धुली हुई थी, उसके सामने की तरफ खून के धब्बे थे। हमारे अनुसार, धोने के बाद सफेद पैंट पर शायद खून के निशान दिख सकते हैं, लेकिन किसी भी मामले में पहले से धुली हुई काली शर्ट पर धब्बे (यदि कोई हो) नंगी आंखों से नहीं दिख सकते।

66. प्रासंगिक रूप से, मृतक के घर की तस्वीरों (प्रदर्श-पी/36 और पी/37) के अवलोकन से पता चलता है कि मृतक के घर का फर्श और चारदीवारी जो लगभग 5 फीट ऊंची है, रेत/मिट्टी से प्लास्टर की गई थी। अभियोजन पक्ष का मानना है कि आरोपी इस दीवार को फांदकर भाग गया था जो लगभग 5 फीट ऊंची है। इसलिए, यदि अपीलकर्ता की शर्ट खून से सनी हुई होती, जैसा कि दावा किया गया है, तो यह निश्चित रूप से मिट्टी और स्थानीय रेत से प्लास्टर की गई दीवार पर खून के निशान छोड़ती।

67. एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/47) मृतक की शर्ट, पैंट, गुदरी, तकिया और बिस्तर की चादर पर मानव रक्त की उपस्थिति को इंगित करती है, साथ ही आरोपी की पैंट और शर्ट और कुल्हाड़ी पर भी। लेकिन, जहां तक ब्लड ग्रुप की बात है, एफएसएल रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक और आरोपी की पैंट पर खून के धब्बे 'एबी' ग्रुप के थे।

68. यह उल्लेखनीय है कि मृतक की शर्ट, गुदरी, तकिया और चादर का रक्त समूह अनिर्णायक बताया गया है। इसी प्रकार अभियुक्त की शर्ट और बरामद की गई कुल्हाड़ी की स्थिति भी अनिर्णायक है। हम समझ सकते हैं कि अभियुक्त की शर्ट के संबंध में रिपोर्ट अनिर्णायक है, क्योंकि वह पहले से ही धुली हुई थी। लेकिन, किसी को आश्चर्य होगा कि जब एफएसएल को भेजे गए आठ नमूनों में से, रक्त से सने सामान (संख्या में छह) का रक्त समूह अनिर्णायक रहा, तो फोरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभियुक्त - अपीलकर्ता की पैंट पर लगे दागों का रक्त समूह कैसे दर्शा सकती है! यह देखते हुए कि अभियुक्त की शर्ट और पैंट बरामद होने पर धुली हुई पाई गई थी और बरामद की गई छह वस्तुओं के संबंध में रिपोर्ट अनिर्णायक है - कि वे खून से सने हुए थे या बिना धुले हुए थे।

69. इसलिए, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता की शर्ट और उसके घर से बरामद कुल्हाड़ी पर रक्त समूह के मिलान के बिना केवल मानव रक्त की उपस्थिति के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट जांच के लिए भेजे गए सभी सामानों के रक्त समूह को इंगित नहीं करती है।

E. अभियुक्त के रक्त समूह की जांच न करवाना:

70. हम एफएसएल रिपोर्ट को खारिज करने के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्कों से बहुत अधिक सहमत नहीं हैं, क्योंकि जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता के रक्त (विशेष रूप से उसके रक्त समूह) का नमूना एकत्र नहीं किया था। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वकील ने तीन निर्णयों का हवाला दिया (जैसा कि पैरा-18 में उल्लेख किया गया है), लेकिन यदि मामले के प्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया जाए, तो हम दृढ़ता से इस विचार पर हैं कि अभियोजन पक्ष का मामला इस आधार पर नहीं आ सकता है।

71. अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि मृतक और आरोपी के बीच कोई लड़ाई हुई थी और न ही हाथापाई के कोई निशान हैं। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था, जब वह सो रहा था और इसलिए, हमलावर का खून बहकर मृतक या आरोपी के शरीर के कपड़ों पर फैलने का सवाल ही नहीं उठता।

72. इस प्रकार, जांच अधिकारी ने आरोपी के रक्त के नमूने न लेकर कोई कानूनी गलती नहीं की है। हमारे अनुसार, यह तथ्य कि आरोपी-अपीलकर्ता का रक्त का नमूना नहीं लिया गया, अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई असर नहीं डालता। भले ही यह मान लिया जाए कि मृतक के सगे भाई अपीलकर्ता का रक्त समूह एक ही है, लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि अपीलकर्ता की पैंट पर उसके अपने खून के निशान होंगे, खासकर तब जब न तो कोई हाथापाई हुई थी और न ही उसे कोई चोट लगी थी। इस उद्देश्य के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उद्धृत सभी निर्णयों में आपसी लड़ाई या हाथापाई का उदाहरण था, जबकि वर्तमान मामले में कोई हाथापाई नहीं हुई थी। इसके अलावा, अभियुक्त अपीलकर्ता ने अपने कपड़ों पर मानव रक्त की उपस्थिति को स्पष्ट करने का विकल्प नहीं चुना है, रक्त समूह की तो बात ही छोड़िए।

F. अंतिम बार देखा गया:

73. अभियुक्त-अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अंतिम बार देखे जाने का घटक ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9) की गवाही से साबित हुआ है। यह देखते हुए कि ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9) का बयान यदि प्रेरित नहीं है तो बढ़ाया गया है, हमें लगता है कि भले ही उसकी गवाही, धारा 161 सीआरपीसी के तहत दिए गए उसके बयान से मेल खाती हो, तब भी अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति को साबित नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि, उसके बयान के अनुसार, ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9) ने अभियुक्त को पिछली रात (29.05.2014) को लगभग 11:30 बजे - 11:45 बजे मृतक के घर से बाहर निकलते देखा था। ऐसा तथ्य, भले ही सच माना जाए, हमारे दृढ़ विचार में, 'अंतिम बार देखा गया' के साक्ष्य को स्थापित करने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है।

74. साइट निरीक्षण रिपोर्ट और कई गवाहों के बयानों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता और मृतक का घर लगभग एक दूसरे के सामने था और इसलिए, यदि अपीलकर्ता मृतक के घर के बाहर घूमता हुआ पाया गया था, तो वह अपने घर के बाहर भी था।

75. जहां तक अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत का संबंध है, स्थापित कानूनी स्थिति यह बताती है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के मामले में, सिद्धांत तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति घटना के निकट किसी भी समय मृतक/पीड़ित के साथ अंतिम बार देखा जाता है, न कि तब जब कोई व्यक्ति घटना स्थल के आसपास देखा जाता है। निस्संदेह, मृतक अपने घर में मृत पाया गया था; ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह सुझाव दे कि यह अपीलकर्ता था, जो मृत्यु से

ठीक पहले मृतक के घर के अंदर गया था। इसके अलावा, ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9) ने कहा कि उसने अपीलकर्ता को मृतक के घर के बाहर घूमते हुए देखा था, न कि उसने अपीलकर्ता को 'हाथ में कुल्हाड़ी लिए' देखा था, जिसे अपराध का हथियार बताया जा रहा है।

76. प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर, हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि वर्तमान मामले में 'अंतिम बार देखा गया' का महत्वपूर्ण घटक उपयुक्त रूप से साबित हुआ है।

77. हम यह देखने में जल्दबाजी करते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अप्रासंगिक विचार और साक्ष्य के गलत मूल्यांकन के आधार पर अभियुक्त-अपीलकर्ता को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया माना है।

78. 'अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत' के आवेदन के संबंध में, निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ देना प्रासंगिक होगा:

79. (2005) 3 एससीसी 114 में रिपोर्ट किए गए उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

> "22. अंतिम बार देखा गया सिद्धांत तब काम आता है जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित देखा गया था और जब मृतक मृत पाया गया था, उसके बीच का समय अंतराल इतना कम है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की संभावना असंभव हो जाती है। कुछ मामलों में यह सकारात्मक रूप से स्थापित करना मुश्किल होगा कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था, जब बीच में लंबा अंतराल हो और अन्य व्यक्तियों के आने की संभावना हो। यह निष्कर्ष निकालने के लिए किसी अन्य सकारात्मक सबूत के अभाव में कि अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार एक साथ देखा गया था, उन मामलों में दोष के निष्कर्ष पर पहुंचना खतरनाक होगा।"

80. 2016 (12) एससीसी 251 में रिपोर्ट किए गए रामब्रक्ष बनाम छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा है:

> "10. यह सामान्य कानून है कि अभियुक्त के खिलाफ केवल इस आधार पर दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती कि अभियुक्त को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था। दूसरे शब्दों में, केवल

अंतिम बार साथ देखे जाने की परिस्थिति के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती। आम तौर पर, अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत तब लागू होता है जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित देखे जाने और मृतक के मृत पाए जाने के बीच का समय अंतराल इतना कम होता है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध करने की संभावना असंभव हो जाती है। दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए, अंतिम बार साथ देखे जाने का आधार ही पर्याप्त नहीं होगा और अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी करनी होगी।"

81. उपर्युक्त अवलोकन को न्यायालयों द्वारा अनेक निर्णयों में दोहराया गया है। [बोध राज उर्फ बोधा एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य : 2002 क्रिएलजे 4664, गोवा राज्य बनाम संजय ठाकरान एवं अन्य : (2007) 3 एससीसी 755, रामरेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य : AIR(2006) एससी 1656 और हट्टी सिंह बनाम हरियाणा राज्य : (2007) 12 SCC 471 भी देखें]

82. कृष्ण कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य : (2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1180) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत से संबंधित उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए निष्कर्ष निकाला था कि अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत इस मामले में लागू नहीं होता है। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

"11. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों से पूछताछ की गई और निर्विवाद तथ्य यह है कि उनमें से किसी ने भी अभियुक्त और मृतक को घटना के दिन किसी विशेष समय पर एक साथ और जीवित देखने की गवाही नहीं दी थी, और न ही उन्हें घटना के निकट किसी भी समय एक साथ और जीवित देखा था।

19. उपरोक्त कमज़ोरी के बावजूद, न्यायालयों ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए उचित सावधानी और सतर्कता नहीं बरती है। हमारी टिप्पणी का कारण तत्काल मामले में किए गए साक्ष्य के मूल्यांकन के एक मात्र अवलोकन से सामने आ जाएगा। हम पहले ही यह पा चुके हैं कि यह पता

लगाने के बाद भी कि मृतक को अभियुक्त के साथ किसी ने नहीं देखा था, ट्रायल कोर्ट ने माना कि चर्चा की गई सामग्री अर्थात पीडब्लू-7, पीडब्लू-8 और पीडब्लू-10 के साक्ष्य मृतक की हत्या से ठीक पहले अभियुक्त के साथ मौजूदगी को दर्शाने के लिए पर्याप्त होंगे।

20. पीडब्लू-10, पीडब्लू-8 और पीडब्लू-7 की मौखिक गवाही और निचली अदालतों द्वारा उनकी समीक्षा के तरीके का मूल्यांकन करने से पहले हम इस प्रश्न पर विचार करना उचित समझते हैं कि क्या 'अंतिम बार देखा गया सिद्धांत', अपने अनुप्रयोग में, मृतक के अभियुक्त के साथ घटना से ठीक पहले मौजूद होने के बारे में अनुमान को खारिज कर सकता है, जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के सकारात्मक प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में, मृतक को अभियुक्त के साथ घटना के समय जीवित देखा था।

21. हमें इसका नकारात्मक उत्तर देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है क्योंकि अन्यथा किसी अन्य सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में 'अंतिम बार देखा गया' के सिद्धांत का अनुप्रयोग यह निष्कर्ष निकालने के लिए खतरनाक होगा कि अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार एक साथ देखा गया था, जैसा कि सतीश के मामले (उपरोक्त) में माना गया है। इसका अप्रत्यक्ष अनुप्रयोग भी अस्वीकार्य है। इस संदर्भ में हट्टी सिंह मामले में इस न्यायालय का निर्णय भी प्रासंगिक है। उस मामले में यह माना गया था कि जब तक मृतक को अभियुक्तों के साथ अंतिम बार देखा जाना और हत्या के बीच का समय अंतराल निकट न हो, केवल उस आधार पर अभियुक्त का अपराध साबित करना मुश्किल होगा।

83. उपरोक्त निर्णयों में की गई टिप्पणियों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत तब लागू किया जा सकता है जब साक्ष्य यह सुझाए कि मृतक को ‘अंतिम बार अभियुक्त के साथ जीवित देखा गया था’।

84. वर्तमान मामले में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह सुझाए कि मृतक को घटना से पहले किसी निकट समय पर अभियुक्त के साथ या “एक साथ और जीवित” देखा गया था। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट पी.डब्लू.9 की गवाही पर अंतिम

बार देखे जाने के सिद्धांत को पेश करने और इस आधार पर दोषसिद्धि को आधार बनाने के लिए गलत तरीके से आगे बढ़ा है।

G. न्यायेतर स्वीकारोक्ति:

85. ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि यह न्यायेतर स्वीकारोक्ति का मामला है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, ट्रायल कोर्ट ने ओम प्रकाश (पी.डब्लू. 9) और निहाल चंद (पी.डब्लू. 11) की गवाही पर विश्वास किया, जिन्होंने यह बयान दिया था कि आरोपी-अपीलकर्ता ने अपने भाई की हत्या करने का अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।

86. इन दो गवाहों के बयानों को सरलता से पढ़ने पर पता चलता है कि जब उन्होंने आरोपी-अपीलकर्ता से सवाल पूछा, "तुमने क्या किया है?", तो अपीलकर्ता ने कथित तौर पर अपने भाई की हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया।

87. इन गवाहों (ओम प्रकाश और निहाल चंद) द्वारा पुलिस को धारा 161 सीआरपीसी के तहत दिए गए बयानों को यदि उन्हें अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत किए गए उनके बयानों (प्रदर्श-डी/1 और डी/2) के साथ जोड़कर पढ़ा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उन्हें प्रेरित नहीं किया गया है, तो उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।

88. (2012) 6 एससीसी 403 में रिपोर्ट किए गए सहदेवन एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायेतर स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता और साक्ष्य मूल्य पर विचार करते हुए, विभिन्न निर्णयों का संदर्भ देते हुए, निम्नानुसार टिप्पणी की:

> 15.1. बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1995 सप (4) एससीसी 259: 1996 एससीसी (क्रि) 59 में इस न्यायालय ने यह सिद्धांत बताया कि: (एससीसी पृष्ठ 265, पैरा 10)
>
> > 10. न्यायेतर स्वीकारोक्ति अपने स्वभाव से ही एक कमज़ोर प्रकार का साक्ष्य है और इसे बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ परखने की आवश्यकता होती है। जहाँ न्यायेतर स्वीकारोक्ति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी होती है, वहाँ इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और यह अपना महत्व खो देती है।
> >
> > x x x x

15.4. न्यायेतर स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता और साक्ष्य मूल्य को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के आयामों की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम राजा राम: (2003) 8 एससीसी 180: 2003 एससीसी (क्रि) 1965 में यह सिद्धांत बताया कि: (एससीसी पृष्ठ 192, पैरा 19)

> 19. यदि कोई न्यायेतर स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और सत्य है तथा मानसिक रूप से स्वस्थ द्वारा की गयी है, तो न्यायालय उस पर भरोसा कर सकता है। स्वीकारोक्ति को किसी अन्य तथ्य की तरह साबित करना होगा। स्वीकारोक्ति के संबंध में साक्ष्य का मूल्य, किसी अन्य साक्ष्य की तरह, उस गवाह की सत्यता पर निर्भर करता है जिसके समक्ष यह स्वीकारोक्ति की गई है।

89. 2011 (12) एससीसी 258 में रिपोर्ट किए गए सुनील राय उर्फ पौआ एवं अन्य बनाम संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामले में, जिस पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने भरोसा किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

> 27. बेशक, कथित इकबालिया बयान मौखिक था और इसे लिखित रूप में दर्ज नहीं किया गया था। बेशक, सुनील राय का पीडब्लू-10 के साथ कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था, और न ही कोई अंतरंगता थी। एक ऐसे व्यक्ति के समक्ष मौखिक रूप से दिया गया न्यायेतर स्वीकारोक्ति इकबालिया बयान, जिसके साथ इकबालिया बयान देने वाले का कोई अंतरंग संबंध नहीं है, बहुत मजबूत सबूत नहीं है और किसी भी स्थिति में इसका इस्तेमाल केवल पुष्टि के लिए किया जा सकता है (एस. अरुल राजा बनाम तमिलनाडु राज्य, (2010) 8 एससीसी 233 पैराग्राफ 48-56 देखें)।
> X X X X X
>
> 28. उपर्युक्त कारणों से हम पीडब्लू-10 के साक्ष्य पर भरोसा करना असंभव पाते हैं और इसी प्रकार, सुनील राय द्वारा दिया गया न्यायेतर स्वीकारोक्ति मौखिक इकबालिया बयान है।

90. हमारे अनुसार, यदि इन गवाहों के बयान पर विश्वास भी कर लिया जाए, तो भी इसे समसामयिक तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर परखने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि अपना अपराध स्वीकार करने वाला बयान अभियुक्त-अपीलकर्ता

द्वारा 05.06.2014 को दिया गया था, जब उसे कुल्हाड़ी और कपड़े बरामद करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा मृतक के घर लाया गया था। हमारे अनुसार, ऐसा उत्तर या प्रतिक्रिया यदि दी भी गई हो, तो उसे निम्नलिखित अनेक कारणों से न्यायेतर स्वीकारोक्ति नहीं कहा जा सकता: (i) अभियुक्त-अपीलकर्ता का ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9) और निहाल चंद (पी.डब्लू.11) के साथ कोई नजदीकी रिश्ता नहीं था, जिसके लिए वह अपना दिल खोलकर सामने आए; (ii) अभियुक्त-अपीलकर्ता के पास इतने सारे ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों की उपस्थिति में अपना अपराध स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था; (iii) वे परिस्थितियाँ जिनमें कथित स्वीकारोक्ति दी गई और अंत में; (iv) स्वीकारोक्ति के समय अपीलकर्ता पुलिस हिरासत में था।

91. पिछले पैराग्राफ में बताए गए कारणों से, हमारा मानना है कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति के बारे में ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष न्यायेतर स्वीकारोक्ति के पहलू पर स्थापित स्थिति के विपरीत है।

(H) मकसद:

92. अभियोजन पक्ष ने सुभाष (पी.डब्लू.2) और ओम प्रकाश (पी.डब्लू.9) को गवाह के कठघरे में लाया था, जिन दोनों ने यह बयान दिया कि मृतक और अभियुक्त-अपीलार्थी के बीच विवाद था। उन्होंने यह बयान दिया कि मृतक अविवाहित था और दोनों भाइयों के बीच तनावपूर्ण संबंध थे और मृतक कभी भी अपीलार्थी के घर नहीं जाता था और यह भी कि अविवाहित होने के बावजूद मृतक न तो अपीलार्थी के घर जाता था और न ही कभी उसके घर पर एक कप चाय पीता था।

93. यह ध्यान देने योग्य है कि इन दो गवाहों और कुछ और गवाहों ने यह गवाही दी कि मृतक ने अपनी जमीन का हिस्सा अभियुक्त-अपीलार्थी को खेती (इजरा) के लिए दे दिया था, लेकिन इन दोनों भाइयों के बीच किसी भी मामले या मुकदमे के लंबित होने का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। यहां तक कि जांच अधिकारी ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि आरोपी-अपीलकर्ता और मृतक के बीच कोई मामला लंबित नहीं था।

94. साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, हमारा मानना है कि शायद गवाहों ने न्यायालय के मन में संदेह का बीज बो दिया है कि तनावपूर्ण संबंधों के कारण अपीलकर्ता ने अपने भाई की हत्या की होगी, लेकिन हत्या के कारण के बारे में ऐसा संदेह मकसद के रूप में नहीं लिया जा सकता है। कारण और मकसद के बीच एक पतली लाइन जैसा, फिर भी स्पष्ट अंतर है। मकसद

बहुत अधिक संभावना को पूर्व निर्धारित करता है, जिसके कारण एक सामान्य व्यक्ति किसी की जान लेने की हद तक जा सकता है।

95. हमें लगता है कि केवल इस तथ्य के कारण कि दो भाई बातचीत नहीं कर रहे थे, यह नहीं माना जा सकता है कि इस तरह के रिश्ते से असंतुष्ट होकर कोई अपने ही भाई की हत्या करने जैसा जघन्य अपराध करेगा। झगड़े, हाथापाई या लंबित मुकदमे का कोई उदाहरण या सबूत नहीं है। मकसद पहले से ही सोची-समझी सोच को पूर्व निर्धारित करता है, जिसके लिए एक आरोपी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी योजना बना सकता है और उसे क्रियान्वित कर सकता है। हमारी राय में, अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष जो कुछ प्रस्तुत किया गया है, वह अधिक से अधिक संदेह का कारण हो सकता है, लेकिन उसे अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के उद्देश्य के दायरे में नहीं लाया जा सकता।

96. यहां रामानंद उर्फ नंदलाल भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1396) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले का लाभप्रद संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों में मकसद की भूमिका को विस्तृत करते हुए, अदालत ने संदेह और मकसद के बीच अंतर किया था और इस प्रकार टिप्पणी की थी:

> 87. यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, अभियुक्त की ओर से अपराध करने का उद्देश्य अधिक महत्व रखता है। इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धांत निर्धारित किया है कि अपराध करने का उद्देश्य निस्संदेह उन मामलों में अधिक महत्व रखता है जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होते हैं, उन मामलों की तुलना में जिनमें अपराध करने के बारे में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। यह भी उतना ही सच है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में उद्देश्य साबित करने में विफलता अपने आप में घातक नहीं है। हालाँकि, यह भी अच्छी तरह से स्थापित है और कानून में यह प्रचलित है कि उद्देश्य की अनुपस्थिति अपराध करने वाली परिस्थितियों की एक गुम कड़ी हो सकती है, लेकिन एक बार जब अभियोजन पक्ष ने अन्य अपराध करने वाली परिस्थितियों को पूरी तरह से स्थापित कर दिया है, तो उद्देश्य की अनुपस्थिति अभियुक्त को कोई लाभ नहीं देगी।

88. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त अपीलकर्ता का मंजू के साथ अवैध संबंध था और वह मंजू से विवाह करके जीवन बसाना चाहता था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पूर्व में अभियुक्त अपीलकर्ता की मंजू से सगाई हो चुकी थी और वह विवाह करने वाला था। प्रासंगिक समय पर जब अभियुक्त अपीलकर्ता की मंजू से सगाई हुई, ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक संगीता सहित सभी लोग सहमति से इसमें शामिल थे। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह इंगित करे कि अभियुक्त अपीलकर्ता की मंजू से सगाई के समय मृतक संगीता ने शोर मचाया हो या अपने पति के ऐसे निर्णय का विरोध किया हो। बेशक, यह बहुत ही व्यक्तिगत मामला है। यदि हम अभियुक्त अपीलकर्ता के मंजू के साथ अवैध संबंध पर विश्वास करते हैं, तो यह संभव है कि मृतक संगीता एक बिल्कुल असहाय महिला हो सकती है और वह इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकती थी। हालाँकि, विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या केवल इस मकसद को ही आरोपी अपीलकर्ता को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराने और उसे मौत की सजा देने के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए।

89. संपत कुमार बनाम पुलिस निरीक्षक कृष्णगिरि, (2012) 4 एससीसी 124, दिनांक 02.03.2012 को निर्णीत मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

> 29. एन.जे. सूरज बनाम राज्य: (2004) 11 एससीसी 346: 2004 एससीसी (क्रि) सप 85] में अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य और मकसद पर आधारित था। अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया, उन पर चर्चा करने के बाद, इस न्यायालय ने मकसद को खारिज कर दिया, जो अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया गया एकमात्र शेष परिस्थिति थी, जिसमें कहा गया था कि मकसद की उपस्थिति दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि यह अच्छी

तरह से स्थापित है कि परिस्थितियों की श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जो एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर ले जाए, जो अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत है।

30..... .....

31. किसी भी मामले में, अकेले मकसद को दोषसिद्धि का आधार नहीं माना जा सकता।

32. रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, अभियुक्त के खिलाफ कुछ संदेह हो सकता है, लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है, संदेह, चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता।

31. यह कहना पर्याप्त है कि यद्यपि अपीलकर्ताओं के अनुसार मृतक सेंथिल को नुकसान पहुँचाने के लिए अपीलकर्ता वेलु के पास कोई उद्देश्य था, क्योंकि वह उसकी बहन उषा के प्रेम में पड़ गया था, लेकिन परिवार द्वारा मृतक सेंथिल से उषा का विवाह करने का निर्णय लेने के बाद उसका कोई औचित्य नहीं रहा। फिर भी यह मानते हुए भी कि अपीलकर्ता वेलु मृतक सेंथिल से उषा का विवाह करने के विचार से सहमत नहीं था, केवल इतना ही कहा जा सकता है कि मृतक को शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाने के लिए अपीलकर्ता वेलु के पास कोई उद्देश्य था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में यह एक महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है, लेकिन यह निर्णायक सबूत की जगह नहीं ले सकती कि संबंधित व्यक्ति ही अपराध का लेखक था। कोई यह भी कह सकता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मकसद की मौजूदगी अपीलकर्ता के खिलाफ एक मजबूत संदेह पैदा करती है, लेकिन संदेह, चाहे कितना भी मजबूत हो, उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध के सबूत का विकल्प नहीं हो सकता।

90. इस प्रकार, भले ही यह माना जाता है कि अभियुक्त अपीलकर्ता के पास अपराध करने का एक मकसद था, यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है, लेकिन यह निर्णायक सबूत के रूप में जगह नहीं ले सकती कि संबंधित व्यक्ति अपराध का लेखक था। कोई यह भी कह सकता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मकसद की मौजूदगी अभियुक्त अपीलकर्ता के खिलाफ एक मजबूत संदेह पैदा करती है, लेकिन संदेह, चाहे कितना भी मजबूत हो, उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध के सबूत का विकल्प नहीं हो सकता।

(I) गिरफ्तारी की वैधता:

97. इस न्यायालय के अनुसार, संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार जांच अधिकारी को यह निर्देश देते हैं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले, उसके पास यह विश्वास बनाने के लिए पर्याप्त मौखिक या प्रत्यक्ष साक्ष्य होना चाहिए, जो कि केवल संदेह या आशंका से अधिक होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति अपराध में शामिल है। ऐसी राय बनाने के बाद, जांच अधिकारी को यह संतुष्ट होना चाहिए कि जांच को आगे बढ़ाने और अपराध से उसे जोड़ने वाले अपेक्षित साक्ष्य की बरामदगी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है।

98. यह सच है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के चरण में, जांच अधिकारी के पास ठोस सामग्री या निश्चित जानकारी होना आवश्यक नहीं है और उचित विश्वास के आधार पर, वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन ऐसा विश्वास संदेह या अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि ठोस और विवेकपूर्ण तर्क पर आधारित होना चाहिए।

99. गवाहों के बयानों सहित अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता को जांच अधिकारी द्वारा 03.06.2014 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि लगभग सभी गवाहों के धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान उसकी गिरफ्तारी के बाद दर्ज किए गए थे। इसके अलावा, उस तिथि (03.06.2014) तक दर्ज किए गए बयानों के अनुसार, केवल यही तथ्य सामने आया था कि दोनों भाई अलग-अलग रहते थे। इसलिए अपीलकर्ता को पूरी तरह से अनुमान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। यह अलग बात है कि उसके

बाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दी गई जानकारी के अनुसार कथित बरामदगी की गई।

100. 03.06.2014 तक जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता के पड़ोसी मंगतू राम नायक (पी.डब्लू.6) और देवी लाल विश्नोई (पी.डब्लू.7) का बयान दर्ज कर लिया था। इन पड़ोसियों ने धारा 161 सीआरपीसी के तहत दिए गए अपने बयानों में बस इतना बताया था कि जब वे अपीलकर्ता के अनुरोध पर मृतक के घर गए, तो उन्होंने पाया कि अपीलकर्ता का व्यवहार सामान्य नहीं था और उन्हें लगा कि अपीलकर्ता को मृतक की हत्या करने वाले व्यक्ति के बारे में पता था। धारा 161 सीआरपीसी के तहत दिए गए इन दोनों व्यक्तियों के बयान क्रमशः प्रदर्श पी/14 और प्रदर्श पी/15 के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। बयान का प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

प्रदर्श पी/14 (मंगतू राम का बयान) :

> "... ... विनोद व राजेश की आपस में नहीं बनती थी इस कारण वह उसके घर भी नहीं आता था ना ही उसके घर से कोई चीज मंगवाता था वह अविवाहित था तो अक्सर अपनी भुआ के घर जाकर रोटी खाता था या लेट हो जाता तो मेरे घर से रोटी मंगवाकर खाता था।... ..."

प्रदर्श पी/15 (देवी लाल का बयान) :

> "... ... राजेश तथा विनोद की आपस में बोलचाल नहीं थी इस कारण वह विनोद के घर नहीं आता जाता था ना ही उसके घर से कोई चीज खाने पीने की लेकर जाता था ... ..."

101. इन बयानों के अवलोकन से पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर कोई यह निष्कर्ष निकाल सके या राय बना सके कि अपीलकर्ता ही वह व्यक्ति था जिसने मृतक की हत्या की थी।

102. आरोप-पत्र के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत करना अनुचित नहीं होगा, जिसमें 03.06.2014 को अपीलकर्ता को गिरफ्तार करने का कारण शामिल है:

> "... ... दिनांक 2.06.2014 मुकदमा हाजा का अनुसंधान मन एसएचओ द्वारा शुरू किया जाकर पूर्व में मामूर मुखवीर से सम्पर्क कर बातचित की तथा तमाम स्थिति व बिन्दुओं के बारें में विस्तृत जानकारी हासिल की गई। मृतक के पड़ौसी मंगतूराम नायक व देवीलाल बिश्नोई से तफ्तीश व ब्यान लिये जाकर इतला देहिन्दा विनोद कुमार जो मृतक का सगा भाई है से पूछताछ करने कर्ता जूर्म को इकबाल करने पर विनोद कुमार को जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द शामिल फाईल की गई। ... ..."

103. आरोप-पत्र के उपरोक्त भाग का अवलोकन करने पर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि केवल इन दो व्यक्तियों अर्थात् मंगतू राम (पी.डब्लू. 6) और देवी लाल (पी.डब्लू. 7) के बयानों के आधार पर ही जांच अधिकारी ने आरोपी-अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी 03.06.2014 को की गई थी और कोई भी ऐसा सबूत या विश्वसनीय जानकारी या संदेह करने का उचित आधार नहीं था, जिससे जांच अधिकारी अपीलकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए प्रेरित हो सके।

104. यदि 03.06.2014 को धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए उपर्युक्त दो व्यक्तियों के बयानों पर विचार किया जाए, तो कोई भी उचित विवेक वाला व्यक्ति यह विश्वास नहीं कर सकता है कि अपीलकर्ता (मृतक का भाई) ने मृतक की हत्या की थी।

105. यह उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण सामग्री या साक्ष्य, चाहे वह अन्य ग्रामीणों या पुष्पा (पी.डब्लू.14) (मृतक की बहन होने के नाते) के बयानों के रूप में हो, अपीलकर्ता की गिरफ्तारी (03.06.2014 को) के बहुत बाद प्राप्त हुए। शेष व्यक्तियों के बयान 5/06 जून और 20 जून के बीच दर्ज किए गए। दिलचस्प बात यह है कि अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाह गवाह बॉक्स में आए और अपने बयान से पलट गए। इसलिए, अपीलकर्ता की गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (i)(ba) के प्रावधानों का पूर्ण उल्लंघन है। हमारे अनुसार बाद में एकत्र किए गए साक्ष्य अन्यथा अवैध और मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी को वैध नहीं ठहरा सकते।

106. चूंकि गिरफ्तारी ही अवैध थी, इसलिए इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए, अपने ही ज्ञात कारणों से, साक्ष्य गढ़े हों या बनाए हों, जैसा कि ऊपर उल्लेखित अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं की पृष्ठभूमि में है।

(J) अपीलकर्ता की ओर से अन्य तर्क:

(i) एक से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति:

107. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चौधरी ने बताया कि घटनास्थल के निरीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि फर्श पर ताश के पत्ते और अन्य कई चीजें बिखरी हुई थीं और तर्क दिया कि इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि मृतक के साथ ताश खेलते समय किसी का झगड़ा हुआ था और इस प्रक्रिया में उसकी हत्या कर दी गई थी। हमारे अनुसार, श्री चौधरी का यह तर्क सही नहीं है क्योंकि फर्श पर पड़े ताश के पत्ते या चीजों की उपस्थिति का यह मतलब नहीं है कि मृतक के अलावा एक से अधिक व्यक्ति मौजूद थे।

108. तीन खरोंच के निशानों की उपस्थिति, जो ताजा बताए गए हैं, को इस तथ्य का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है कि तीन व्यक्ति मृतक के घर में घुसे थे, लेकिन ऐसे निशान मृतक के अलावा और भी व्यक्तियों की उपस्थिति की संभावना के बारे में मन में संदेह पैदा करते हैं।

(ii) अभियुक्त ने स्वयं घटना की सूचना दी:

109. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिया गया अन्य तर्क कि अपीलकर्ता ने ही घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी थी और इसलिए वह निर्दोष है, हमें ज्यादा पसंद नहीं आया। घटना के बारे में पुलिस को सूचना देने के आचरण को निर्दोषता के सबूत के रूप में नहीं लिया जा सकता। अपराध करने के बाद कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना/शिकायत कर सकता है ताकि पुलिस का ध्यान बंट जाए और उसका ध्यान उससे हट जाए।

(iii) चोट का आकार:

110. अपीलकर्ता के वकील के अनुसार, रिकवरी मेमो और जांच अधिकारी के बयान में कुल्हाड़ी का आकार 11.5 सेमी दर्शाया गया है, जबकि चोट रिपोर्ट में दिए गए घाव का आकार और डॉक्टर (पी.डब्लू.12) के बयान के अनुसार घाव का आकार 1 इंच है और यदि चोट अपीलकर्ता से बरामद कुल्हाड़ी से लगी होती, तो चोट का आकार कुल्हाड़ी के लोहे वाले हिस्से के लगभग आकार के बराबर होता।

111. हम देख सकते हैं कि हालांकि डॉक्टर (पी.डब्लू.12) के बयान से ऐसा आभास होता है कि मृतक के सिर के दाहिनी ओर चार चोटें थीं और प्रत्येक चोट लगभग एक इंच लंबी थी, जिसे तेज धार वाले हथियार से लगाया गया था और यह गंभीर प्रकृति की थी, लेकिन बयान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा आभास ओवरराइटिंग या टाइपोग्राफिकल त्रुटि के कारण है। अन्यथा, चोट रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक नज़र डालने से पता चलता है कि चोट संख्या 4 4' x 2½' x 2' इंच की है।

112. हमारे अनुसार, चोट संख्या 4 जिसकी लंबाई 4 इंच (लगभग 10.2 सेमी) है, वह अपीलकर्ता से बरामद कुल्हाड़ी के कारण हो सकती है और इसलिए, केवल इस कारण कि अन्य तीन चोटें आकार में छोटी हैं (1½; 1 और 1), यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें बरामद किए गए अपराध के हथियार से मेल नहीं खाती हैं।

(iv) दीवार पर खून के धब्बे नहीं:

113. यह न्यायालय श्री चौधरी के इस तर्क में कुछ बल पाता है कि यदि अभियुक्त-अपीलकर्ता की शर्ट बरामद होने पर सामने की तरफ से खून के धब्बे पाई गई थी, तो मृतक के घर की दीवार जो लगभग 5 से 6 फीट है और जिस दीवार से, जांच का दावा है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता हत्या करने के बाद भाग गया था, साफ या खून के निशान के बिना नहीं रह सकती है। हमारा मानना है कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी कि अभियुक्त चारदीवारी फांदकर भाग गया था और मृतक की हत्या करते समय खून के छींटे पड़ गए थे और अपीलकर्ता की शर्ट और पैंट पर खून के धब्बे लग गए थे, सही है, तो निश्चित रूप से कपड़ों पर खून के ऐसे निशान/धब्बे चारदीवारी पर कुछ निशान छोड़ गए होंगे, जिसे मिट्टी/रेत से रंगा गया था।

114. अंतिम टिप्पणी के रूप में यह न्यायालय यह पेश करना चाहता है कि मौजूदा मामले में, अभियुक्त-अपीलकर्ता की दोषीता की ओर इशारा करने वाले किसी भी आपत्तिजनक सामग्री या साक्ष्य के बिना, अभियुक्त-अपीलकर्ता की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी के बाद साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। इसके अलावा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दी गई तथाकथित जानकारी के आधार पर, न केवल बरामदगी की गई है, बल्कि अपीलकर्ता की हिरासत में रहते हुए इकबालिया बयान भी प्राप्त किया गया है। इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि अपीलकर्ता को कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था और कपड़ों की बरामदगी और कुल्हाड़ी रखी गई थी, खासकर तब जब एकत्र और बरामद की गई छह वस्तुओं का रक्त समूह मेल नहीं खाता (आरोपी की पैंट के मामले को छोड़कर)।

(v) बयान दर्ज करने में देरी:

115. हम श्री चौधरी द्वारा बयान दर्ज करने में देरी के बारे में दिए गए तर्क से बहुत अधिक सहमत नहीं हैं, हालांकि यह तर्क बहुत कमजोर था। तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, महावीर (पीडब्लू.15) और राम चंद्र (पीडब्लू.16) जैसे गवाहों के बयान दर्ज करने में 20-30 दिनों की देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं कही जा सकती।

(vi) डॉग स्क्वायड की रिपोर्ट को दबाना :

116. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जांच अधिकारी ने घटनास्थल पर डॉग स्क्वायड को बुलाया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट उन कारणों से पेश नहीं की गई जो उसे ही पता हैं। डॉग स्क्वायड की रिपोर्ट को रोके रखना एक ओर जांच की निष्पक्षता पर संदेह पैदा करता है और दूसरी ओर इस परिकल्पना को बल देता है कि यदि अपीलकर्ता मृतक की हत्या में शामिल था, तो प्रशिक्षित कुत्तों को उसकी पहचान करनी चाहिए थी। ऐसा विचार हमें अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देने का एक और कारण देता है।

निष्कर्ष

117. तथ्यात्मक मैट्रिक्स के विश्लेषण के परिणामस्वरूप और मौखिक और प्रत्यक्ष साक्ष्य के माध्यम से आगे बढ़ने के बाद, हम मानते हैं कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के मामले में आवश्यक तत्वों को संतोषजनक ढंग से साबित करने में सक्षम नहीं रहा है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शरद बिरधीचंद सारदा (उपरोक्त) के मामले में निष्कर्ष निकाला है।

118. अभियोजन पक्ष के मामले में नीचे दिए गए अनुसार बहुत सी खामियाँ और कमियाँ हैं:

(i) किसी ने भी मृतक के साथ अभियुक्त को अंतिम बार नहीं देखा था - वह मृतक के घर के बाहर टहलता हुआ पाया गया था, जो स्वयं अभियुक्त-अपीलकर्ता के घर का बाहर भी है;

(ii) अभियोजन पक्ष मृतक की हत्या करने के लिए अभियुक्त अपीलकर्ता के साथ मकसद को संतोषजनक ढंग से साबित करने में विफल रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक कमजोर संदेह उठाया गया है। ऐसा संदेह दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(iii) मृतक का रक्त समूह अपीलकर्ता की शर्ट पर पाए गए खून के धब्बों और उसकी निशानदेही पर बरामद की गई कुल्हाड़ी के रक्त समूह से मेल नहीं खाता था;

(iv) 03.06.2014 को जब अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया गया था, तब अपराध में उसकी संलिप्तता की ओर इशारा करने वाली कोई सामग्री नहीं थी;

(v) अवैध और मनमानी गिरफ्तारी के बाद इकबालिया बयान दिया गया है और बरामदगी की गई है;

(vi) तथाकथित गलती की स्वीकृति न्यायेतर इकबालिया बयान नहीं है और इसलिए भी कि ऐसा न्यायेतर इकबालिया बयान पुलिस हिरासत में दिया गया था;

(vii) आरोप-पत्र के साथ प्रस्तुत अधिकांश बयान और साक्ष्य अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के बाद एकत्र किए गए थे;

(viii) मृतक के घर की चारदीवारी पर तीन खरोंच के निशान की उपस्थिति, जो मिट्टी से लिपी हुई है, यह दर्शाती है कि घटनास्थल से तीन या एक से अधिक व्यक्ति भाग गए थे;

(ix) चारदीवारी पर खून के निशान न होना अस्पष्ट है, क्योंकि अपीलकर्ता की शर्ट और पैंट के सामने वाले हिस्से पर खून के धब्बे थे;

(x) यद्यपि अपीलकर्ता उस समय मौजूद था जब डॉग स्क्वायड को बुलाया गया था, लेकिन प्रशिक्षित कुत्तों ने अपीलकर्ता की पहचान नहीं की; और

(xi) जांच अधिकारी ने डॉग स्क्वायड की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया।

119. अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त कारणों और चूकों को देखते हुए, हमें लगता है कि साक्ष्य की श्रृंखला के छल्ले ठीक से बंधे नहीं हैं - "वे एक पतले धागे से बंधे हैं, एक कमजोर आधार पर स्थिर हैं और फिसलन वाली जमीन पर टिके हुए हैं, जो न तो अपीलकर्ता के तर्कों के बल का सामना करने में सक्षम हैं और न ही वे कानूनी सिद्धांतों के लेंस के साथ न्यायिक स्कैनिंग को पार करने में सक्षम हैं"।

120. हमारे अनुसार अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि मृतक राजेश की हत्या अपीलकर्ता ने ही की थी, किसी और ने नहीं।

121. अतः वर्तमान आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपगढ़, कैम्प घड़साना, जिला श्रीगंगानगर द्वारा पारित दिनांक 22.09.2017 के निर्णय को निरस्त और अपास्त किया जाता है।

122. अपीलकर्ता विनोद कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। वह हिरासत में है। यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाएगा।

123. तथापि, धारा 437-ए सीआरपीसी के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बरी किए गए आरोपी अपीलकर्ता को विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष 40,000/- रुपये की राशि का व्यक्तिगत बांड और समान राशि का जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा कि वर्तमान निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्थिति में, इसकी सूचना प्राप्त होने पर, अपीलकर्ता सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी), जे **(दिनेश मेहता), जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।